

प्रारंभिक परीक्षा

पीएम स्वनिधि(PM SVANidhi)

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी।

हाल में क्या परिवर्तन हुए हैं?

- ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई (पहले यह 31 दिसंबर 2024 थी)।
- 1.15 करोड़ लाभार्थियों (50 लाख नए विक्रेताओं सहित) को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- **बढ़ी हुई ऋण सीमाएँ:**
 - पहला ऋण: ₹15,000 (₹10,000 से ↑)
 - दूसरा ऋण: ₹25,000 (₹20,000 से ↑)
 - तीसरा ऋण: ₹50,000 (अपरिवर्तित)
- **यूपीआई-लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड:** दूसरे ऋण के पुनर्भुगतान के बाद जारी किया गया → आपातकालीन ऋण तक त्वरित पहुंच।
- **डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन:** डिजिटल लेनदेन (यूपीआई के माध्यम से खुदरा/थोक) के लिए ₹1,600 तक।
- **क्षमता निर्माण उपाय:** वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, डिजिटल कौशल, विपणन में प्रशिक्षण।
 - **FSSAI** साझेदारी के माध्यम से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण।

योजना के बारे में -

- **लॉन्च:** जून 2020 (कोविड-19 राहत उपाय)।
- **प्रकार:** केन्द्रीय क्षेत्र योजना (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित)।
- **नोडल मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन भागीदार:**
 - आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (समग्र)।
 - वित्तीय सेवा विभाग (DFS) (बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है)।
- **उद्देश्य:**
 - शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को बिना जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना
 - डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
 - विक्रेताओं को पहचान एवं मान्यता प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** वे रेहड़ी-पटरी वाले/हॉकर्स जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे (कट-ऑफ तिथि)

स्रोत: [पीआईबी](#)

राष्ट्रपति की शक्ति: राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल घटाने के संबंध में

संदर्भ

- जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा की चार सीटें फरवरी 2021 से रिक्त हैं, जब केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अधीन था।
 - चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को सुझाव दिया कि जब चुनाव हों, तो राष्ट्रपति इन 4 सदस्यों के कार्यकाल को अलग-अलग कर सकते हैं, ताकि वे सभी 6 साल बाद एक साथ सेवानिवृत्त न हों (1/3 सेवानिवृत्ति प्रणाली को बनाए रखने के लिए)।

राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल घटाने की राष्ट्रपति की शक्ति -

- राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (अनुच्छेद-83)।
- कार्यकाल घटाने का प्रावधान: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 154 के तहत:
 - 1952 में राज्यसभा के प्रथम गठन के समय राष्ट्रपति को (निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद) यह विशेष अधिकार दिया गया था कि वे सदस्यों का कार्यकाल इस प्रकार तय करें कि हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हों।
 - 1956 में पुनः, सातवें संशोधन अधिनियम के तहत, राष्ट्रपति ने कार्यकाल समायोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया।
 - यह शक्ति केवल प्रारंभिक गठन और पुनर्गठन के लिए ही थी — ताकि क्रमिक सेवानिवृत्ति की व्यवस्था स्थापित की जा सके।
- वर्तमान सीमा:
 - विधि मंत्रालय (2024) ने स्पष्ट किया कि अब कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे राष्ट्रपति 1952 और 1956 के बाद कार्यकाल को क्रमिक रूप से निर्धारित कर सकें।
 - वर्तमान रिक्तियां (जैसे J&K की 4 सीटें) राष्ट्रपति आदेश से समायोजित नहीं की जा सकतीं; सभी नए सदस्य पूर्ण 6 वर्षीय कार्यकाल ही पूरा करेंगे।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

यूरोप ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध प्रक्रिया शुरू की

संदर्भ

- ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी (E3) ने संयुक्त राष्ट्र में सैन्यबैक मैकेनिज्म का आह्वान किया, तथा JCPOA का उल्लंघन करने के लिए ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाने हेतु 30 दिन की प्रक्रिया शुरू की।
 - यह कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस के वीटो को दरकिनार कर देता है।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) - 2015

- यह ईरान और विश्व शक्तियों के समूह P5+1 के बीच हुआ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता है।
 - P5: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन
 - +1 = जर्मनी
- JCPOA की मुख्य शर्तें:
 - ईरान केवल 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन करने पर सहमत हुआ (जो परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक ~90% से बहुत कम है)।
 - यूरेनियम भंडार को लगभग 98% घटाकर ~10,000 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक सीमित करने पर सहमति हुई।
 - फोर्दो भूमिगत सुविधा का 15 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
 - IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) को सभी परमाणु स्थलों तक पूर्ण पहुँच प्रदान की गई।
 - इसके बदले अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटाए गए।

संबंधित तथ्य

- 2018 में, डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका JCPOA से हट गया और प्रतिबंधों को पुनः लागू कर दिया।



FDI-आधारित निवेश मॉडल

संदर्भ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स दिग्गजों (Amazon, Walmart-Flipkart) और भारतीय MSMEs के साथ परामर्श शुरू किया है ताकि ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मॉडल खोजे जा सकें।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) -

- किसी अनिवासी द्वारा किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत उपकरणों (शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमन्य शेयर) के माध्यम से किया गया निवेश।
- शर्तें:
 - असूचीबद्ध कंपनी → विदेशी द्वारा किया गया कोई भी इक्विटी निवेश।
 - सूचीबद्ध कंपनी → निर्गम-पश्चात चुकता इक्विटी पूंजी का 10% या अधिक निवेश (पूर्णतः तनुकृत आधार पर)
- प्रकृति: दीर्घकालिक, गैर-ऋण सृजन पूंजी प्रवाह।
- यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के समान नहीं है, जो <10% इक्विटी, अल्पकालिक और अस्थिर होता है।
- कौन से उपकरण FDI के रूप में गिने जाते हैं?
 - FDI में शामिल:
 - विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCBs) → जब इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है।
 - विदेशी संस्थागत निवेश (FII) → यदि यह FDI शर्तों को पूरा करता है (सूचीबद्ध इक्विटी में $\geq 10\%$)।
 - ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स (GDRs) / अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स (ADR) → यदि अंतर्निहित भारतीय इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाता है।
 - FDI में शामिल नहीं:
 - अनिवासी बाह्य (NRE) जमा → ये बैंक जमा हैं, पूंजी/इक्विटी निवेश नहीं → इन्हें बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)/पूंजी खाता प्रवाह के अंतर्गत गिना जाता है, FDI के अंतर्गत नहीं।
- भारत में FDI के मार्ग:
 - स्वचालित मार्ग: कोई पूर्व अनुमोदन नहीं; केवल RBI रिपोर्टिंग।
 - उदाहरण: कृषि, वायु परिवहन सेवाएँ, ऑटोमोबाइल, ग्रीनफील्ड बायोटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण विकास, आदि।
 - सरकारी मार्ग: संबंधित मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
 - उदाहरण: बैंकिंग (सार्वजनिक क्षेत्र), मल्टी-ब्रांड रिटेल, खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार, डिजिटल समाचार अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग, प्रिंट मीडिया, रक्षा (74% से अधिक)।
- FDI के लिए निषिद्ध क्षेत्र:
 - परमाणु ऊर्जा उत्पादन।
 - जुआ और सट्टा, लॉटरी।
 - चिटफंड, निधि कम्पनियां।
 - रियल एस्टेट व्यवसाय (निर्माण को छोड़कर)।
 - सिगार/सिगरेट/तम्बाकू का विनिर्माण।

ई-कॉमर्स के FDI-आधारित मॉडल -

- इन्वेंटरी-आधारित मॉडल: ई-कॉमर्स इकाई माल की इन्वेंटरी का मालिक होती है और सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है।

- **मार्केटप्लेस मॉडल:** ई-कॉमर्स संस्था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म (मार्केटप्लेस) प्रदान करती है जहाँ स्वतंत्र विक्रेता अपने सामान सूचीबद्ध करते हैं। यह प्लेटफॉर्म केवल खरीदार और विक्रेता के बीच एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है।
- **भारत में कौन सा मॉडल उपलब्ध है?**
 - **अनुमत:** मार्केटप्लेस मॉडल (100% FDI अनुमत)।
 - **कारण:** ऑनलाइन दिग्गजों को इन्वेंट्री को नियंत्रित करके छोटे खुदरा विक्रेताओं पर अनुचित रूप से हावी होने से रोकना।
 - **निषिद्ध:** इन्वेंटरी-आधारित मॉडल

भारत में FDI का विनियमन -

- **कानूनी ढांचा:**
 - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** → विदेशी मुद्रा और सीमा पार निवेश को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानून।
 - **FEMA (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019** → FDI, FPI, एलएलपी निवेश, डिपॉजिटरी रसीदें आदि के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित करता है।
 - **समेकित FDI नीति, 2020** → DPIIT (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) द्वारा जारी; समय-समय पर अद्यतन।
- **नियामक प्राधिकरण:**
 - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत में FDI का मुख्य नियामक है।
 - आरबीआई FDI नियमों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



स्कूली शिक्षा पर UDISE+ डेटा

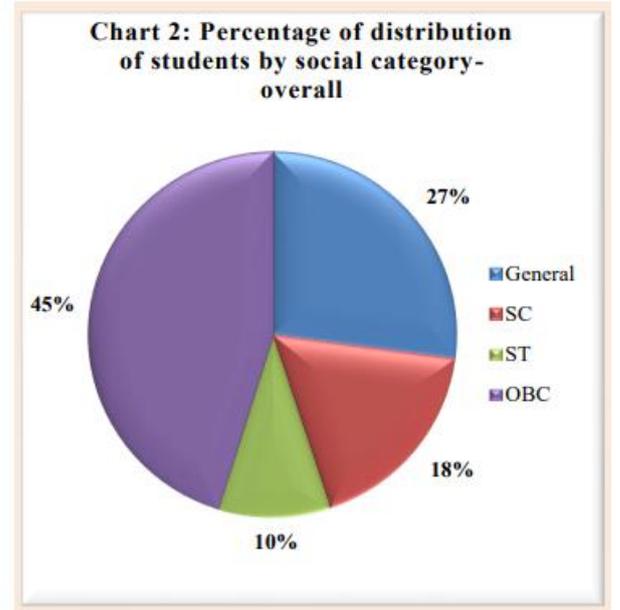
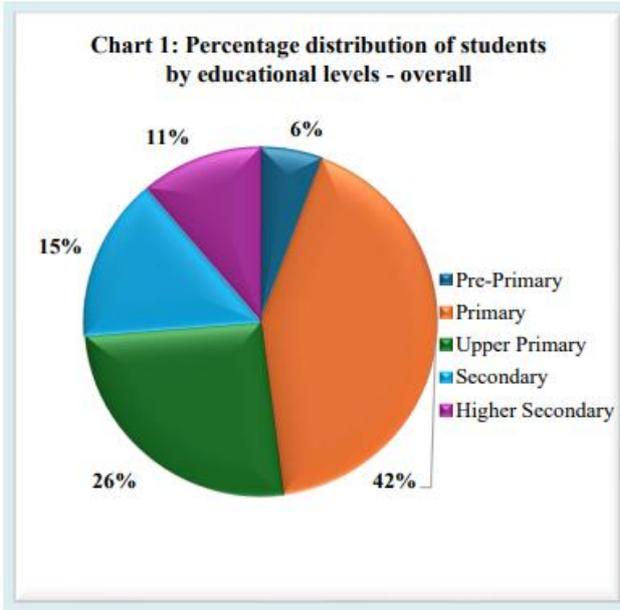
संदर्भ

नवीनतम UDISE+ आंकड़ों के अनुसार, 3-11 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूल नामांकन 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 25 लाख कम हो गया।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) -

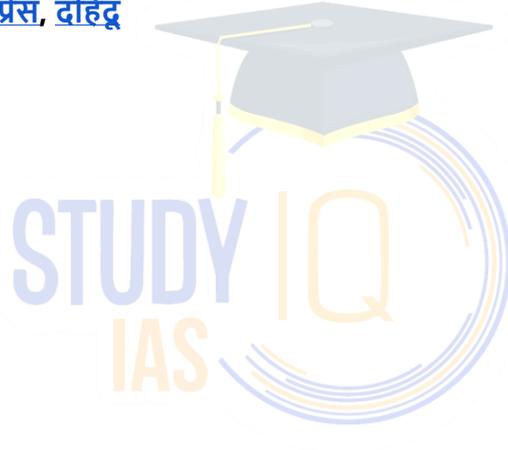
- UDISE+ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- यह भारत का सबसे बड़ा शिक्षा डेटा प्लेटफॉर्म है।
- स्कूल इसका उपयोग निम्नलिखित के बारे में डेटा रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने के लिए करते हैं:
 - स्कूल प्रोफाइल (बुनियादी ढांचा और सुविधाएं)
 - छात्रों का विवरण
 - शिक्षकों का विवरण
- यह वास्तविक समय मोड में काम करता है, तथा विशेष शिक्षा सहित पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को कवर करता है।
- शैक्षणिक वर्ष स्तर पर प्रतिवर्ष डेटा एकत्र किया जाता है।
- डेटा सत्यापन का कार्य ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एमआईएस अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- निगरानी चार स्तरों पर की जाती है - स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय।
- स्कूली शिक्षा की योजना, नीति-निर्माण और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।

डेटा और अंतर्दृष्टि -



- **कुल नामांकन में गिरावट:**
 - कक्षा 1-12 में नामांकन 11 लाख घटकर 24.8 करोड़ (2023-24) से 24.69 करोड़ (2024-25) हो गया।
 - 2018-19 के बाद से सबसे कम।
- **3-11 आयु वर्ग:**
 - आंगनवाड़ी, प्री-स्कूल और कक्षा 1-5 में नामांकन में 25 लाख की गिरावट आई।
- **दीर्घकालिक रुझान:**
 - 2012-13: 26.3 करोड़ छात्र

- 2021-22: 26 करोड़ छात्र
 - 2022-23: 25.18 करोड़
 - 2023-24: 24.8 करोड़
 - 2024-25: 24.69 करोड़ (अब तक का सबसे कम)।
 - **गिरावट का कारण:**
 - जन्म दर में गिरावट (भारत की टीएफआर 2021 में घटकर 1.91 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है)।
 - प्रणाली में प्रवेश करने वाले स्कूली आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम है।
 - **उच्च कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि:**
 - कक्षा 6-8: +6 लाख छात्र (कुल 6.36 करोड़)।
 - कक्षा 9-12: +8 लाख छात्र (कुल 6.48 करोड़)।
 - **सकल नामांकन अनुपात (GER):**
 - मध्य स्तर: 89.5% → 90.3% (2023-24 से 2024-25)।
 - माध्यमिक स्तर: 66.5% → 68.5% (2023-24 से 2024-25)।
 - **स्कूल छोड़ने की दर (सुधार हुआ):**
 - प्रारंभिक चरण: 3.7% → 2.3%
 - मिडिल स्कूल: 5.2% → 3.5%
 - माध्यमिक विद्यालय: 10.9% → 8.2%
- स्रोत: [UDISE+](#), [इंडियनएक्सप्रेस](#), [दहिंदू](#)



इसरो की 5 प्रौद्योगिकियां निजी कंपनियों को हस्तांतरित

संदर्भ

इसरो ने व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए IN-SPACE के माध्यम से अपनी पांच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को भारतीय निजी फर्मों को हस्तांतरित कर दिया।

इसरो की 5 प्रौद्योगिकियां निजी कंपनियों को हस्तांतरित -

- **लो टेम्परेचर को-फायर्ड सेरामिक (LTCC) मल्टी-चिप मॉड्यूल**
 - विकसित: **स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC)**
 - कार्य: कई सेमीकंडक्टर चिप्स को एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल में एकीकृत करता है।
 - हस्तांतरण: **वोल्टिक्स सेमिकॉन प्रा. लि., पुणे** (बायोमैडिकल किट जैसे RT-PCR के लिए)।
- **RTV सिलिकॉन सिंगल-पार्ट एडहेसिव (SILCEM R9)**
 - विकसित: **विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC)**
 - कार्य: सौर पैनल बॉन्डिंग के लिए प्रयुक्त रूम-टेम्परेचर क्योर होने वाला चिपकाने वाला पदार्थ।
 - हस्तांतरण: **क्रेस्ट स्पेशियलिटी रेजिन्स प्रा. लि., अहमदाबाद**।
- **फिल्म एडहेसिव्स EFA 1753 और EFA 1752**
 - विकसित: **VSSC**
 - कार्य: औद्योगिक कॉम्पोजिट अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त।
 - हस्तांतरण: **अज़िस्ता कॉम्पोजिट्स प्रा. लि., हैदराबाद**।
- **30W HMC DC-DC कन्वर्टर**
 - विकसित: **यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC)**
 - कार्य: अंतरिक्ष/औद्योगिक उपयोग के लिए पावर कन्वर्टर।
 - हस्तांतरण: **अनंत टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि., हैदराबाद**।
- **3D प्रिंटेड Al-10Si-Mg मिश्रधातु की एनोडाइजेशन तकनीक**
 - विकसित: **URSC**
 - कार्य: एयरोस्पेस और औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष सतह उपचार तकनीक।
 - हस्तांतरण: **पुष्पक एयरोस्पेस इंडिया प्रा. लि., बंगलुरु**।

स्रोत: [द हिंदू](#)

समाचार संक्षेप में

<p>ब्राइट स्टार अभ्यास 2025</p>	<p>समाचार? भारत 28 अगस्त से 10 सितंबर, 2025 तक 'ब्राइट स्टार 2025' में भाग लेने के लिए तैयार है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यह क्या है? <ul style="list-style-type: none"> ○ 1980 से मिस्र द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक, बहुपक्षीय त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास। ○ इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक माना जाता है। ● उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> ○ भागीदार देशों के बीच संयुक्तता और अंतर-संचालनशीलता को बढ़ाना। ○ आधुनिक युद्ध के परिचालन समन्वय, योजना और निष्पादन में सुधार करना। ○ रक्षा सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना। ● भारत की भागीदारी: <ul style="list-style-type: none"> ○ पहली बार 2023 में भाग लिया; 2025 में भी 700 से अधिक सशस्त्र बल कर्मियों के साथ भागीदारी जारी। ○ गतिविधियों में लाइव फायरिंग, कमांड पोस्ट अभ्यास, लघु प्रशिक्षण ड्रिल और विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद शामिल।
<p>गंगोत्री ग्लेशियर</p>	<p>समाचार? आईआईटी इंदौर, ICIMOD(नेपाल) और अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 1980-2020 के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर प्रणाली (Gangotri Glacier System, GGS) में स्नोमैल्ट (बर्फ के पिघलने से बनने वाला पानी) का प्रवाह लगभग 10% कम हो गया है।</p> <p>गंगोत्री ग्लेशियर अध्ययन (1980-2020) के प्रमुख निष्कर्ष -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रवाह संरचना (औसत 40 वर्ष) <ul style="list-style-type: none"> ○ बर्फ पिघलना = 64% (प्रमुख स्रोत) ○ ग्लेशियर पिघलना = 21% ○ वर्षा-अपवाह = 11% ○ आधार प्रवाह (भूजल) = 4% ● बर्फ पिघलने के हिस्से में गिरावट <ul style="list-style-type: none"> ○ 1980-1990 → 73% ○ 2000-2010 → 52% (बड़ी गिरावट) ○ 2010-2020 → 63% (ठंडी, गीली सर्दियों के कारण आंशिक सुधार) <p>गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में मुख्य तथ्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्थान: उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड (मध्य हिमालय, गढ़वाल क्षेत्र)। ● लंबाई: लगभग 30 किमी (हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक)। ● नदी का उद्गम: भागीरथी नदी (गंगा की मुख्य धारा) का स्रोत। ● पोषक हिमनद: रक्तवर्ण, चतुरंगी, कीर्ति आदि सहायक हिमनदों द्वारा पोषित।
<p>कुशोक बकुला रिनपोछे</p>	<p>समाचार? कुशोक बकुला रिनपोछे पर एक वृत्तचित्र का प्रीमियर 27 अगस्त 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC), नई दिल्ली में हुआ।</p> <p>उनके बारे में -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लद्दाख के एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, राजनेता और राजनयिक, जिन्हें अर्हत बकुला (बुद्ध के 16 शिष्यों में से एक) का अवतार माना जाता है।

	<ul style="list-style-type: none"> • पेशुप गोम्पा, स्पितुक (लद्दाख) के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में सेवा की। • मंगोलिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया (1990-2000/2001), जहां उन्होंने साम्यवाद के तहत दशकों के दमन के बाद बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। • मठों के निर्माण, भारत-मंगोलिया मैत्री को बढ़ावा देने और रूस और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। <p>स्रोत: पीआईबी</p>
<p>भारत में ब्लूबेरी उत्पादन</p>	<p>समाचार? भारत में ब्लूबेरी की खेती जोर पकड़ रही है, हालांकि आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन न्यूनतम है।</p> <p>ब्लूबेरी उत्पादन पर तथ्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत में सालाना लगभग 2,000-3,000 टन ब्लूबेरी का उत्पादन होता है। • ब्लूबेरी की खेती में अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र (विशेष रूप से पुणे और नासिक), कर्नाटक (नीलगिरी हिल्स), हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु (ऊटी और कोडईकनाल), और उत्तराखंड (देहरादून और नैनीताल) शामिल हैं। • भारत चिली, पेरू और पनामा जैसे देशों से सालाना 20,000 टन से अधिक ब्लूबेरी का आयात करता है। <p>ब्लूबेरी की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ब्लूबेरी के लिए ठंडी जलवायु, अम्लीय और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी (पीएच 4.5-5.5), उच्च कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण सूर्य प्रकाश और ड्रिप सिंचाई की आवश्यकता होती है, और कई किस्मों के लिए ठंडे घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।
<p>राजा पृथु</p>	<p>समाचार? असम सरकार ने गुवाहाटी के एक नए फ्लॉइओवर का नाम राजा पृथु के नाम पर रखने का फैसला किया है।</p> <p>राजा पृथु के बारे में -</p> <ul style="list-style-type: none"> • राजा पृथु (जिन्हें पृथु राय या पृथु सिंह भी कहा जाता है) कामरूप (असम क्षेत्र) के 13वीं सदी के शासक थे। • राजवंश: वे खेन राजवंश से संबंध रखते थे, जिसने वर्तमान असम के कुछ हिस्सों पर शासन किया। • ऐतिहासिक संदर्भ: वे दिल्ली सल्तनत के तुर्क-अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध हुए। • बख्तियार खिलजी से युद्ध: <ul style="list-style-type: none"> ○ लगभग 1205-1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने असम के रास्ते तिब्बत पर कब्जा करने के लिए अभियान चलाया। ○ कामरूप में राजा पृथु की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया। ○ खिलजी की सेना स्थानीय हमलों, बीमारियों और अपरिचित भूभाग के कारण कमजोर पड़ गई। ○ अंततः बख्तियार खिलजी पराजित हुआ और पीछे हट गया, तथा शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। <p>स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस</p>

संपादकीय सारांश

जलवायु परिवर्तन, पश्चिमी विक्षोभ और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन और बदलते पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अभूतपूर्व तनाव का सामना कर रहा है, जिसके कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। 2025 में जम्मू में आई दुखद बाढ़ (वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों की 40 से ज़्यादा मौतें) इस संकट की ताज़ा याद दिलाती है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन -

- **मौसम पैटर्न में बदलाव:** पश्चिमी विक्षोभ (WD) अब गैर-परंपरागत महीनों में घटित होते हैं, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून से टकराते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र बादल फटते हैं और भारी वर्षा होती है।
 - उदाहरण: आईएमडी ने 2025 के मानसून के दौरान 14 पश्चिमी विक्षोभ दर्ज किए, जो इस मौसम के लिए असामान्य रूप से उच्च है।
- **हिमालय के ग्लेशियर वैश्विक औसत से दोगुनी गति से पिघल रहे हैं;** 2023 आईसीआईएमओडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान तापमान वृद्धि के कारण 2100 तक 75% ग्लेशियर लुप्त हो सकते हैं।
 - **परिणाम:** हिमनद झीलों का बढ़ना और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का अधिक बार आना (उदाहरण के लिए, सिक्किम का दक्षिण ल्होनक जीएलओएफ, अक्टूबर 2023)।
- **भूस्खलन और चट्टानें गिरना:** लगातार चट्टानों का पुनःनिर्माण + अत्यधिक वर्षा ढलानों को अस्थिर कर देती है।
 - उदाहरण: हिमाचल प्रदेश में 2023 मानसून के दौरान 150 से अधिक भूस्खलन हुए, जिनमें लगभग 400 लोग मारे गए।
- **जल विज्ञान संबंधी चरम सीमाएँ:** नदी व्यवस्था में परिवर्तन: अधिक अचानक बाढ़ (उदाहरण के लिए, चमोली आपदा 2021, चट्टान-बर्फ हिमस्खलन + हिमनद पिघलने से उत्पन्न)।
- **जैव विविधता एवं आजीविका पर प्रभाव:** अल्पाइन वनस्पतियों का ऊपर की ओर स्थानांतरण; हिम तेंदुए और हिमालयी मोनाल जैसी प्रजातियों के लिए आवास में परिवर्तन।
 - उदाहरण: कुटकी और जटामांसी जैसे औषधीय पौधों का उपयोग कम हो रहा है।

परिवर्तनों के पीछे के कारण -

जलवायु/प्राकृतिक चालक

- **ग्लोबल वार्मिंग और नमी लोडिंग:** गर्म हवा में अधिक जल वाष्प होती है → पश्चिमी विक्षोभ-मानसून संपर्क के दौरान भारी वर्षा।
- **जेट स्ट्रीम परिवर्तनशीलता:** जलवायु परिवर्तन जेट स्ट्रीम प्रवाह को बदल देता है → पश्चिमी विक्षोभ ट्रैक को और दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर देता है, जिससे हिमालय में असामान्य वर्षा होती है।
- **ग्लेशियर पिघलना और पर्माफ्रॉस्ट पिघलना:** ग्लेशियरों का तेजी से पीछे हटना ढलानों को कमजोर कर देता है, जिससे उनके ढहने का खतरा बढ़ जाता है।
- **हिम-अल्बेडो फीडबैक:** कम बर्फ कवर से परावर्तन कम हो जाता है, जिससे ऊष्मा अवशोषण बढ़ जाता है → ग्लेशियर का और पीछे हटना।

मानवजनित चालक

- **अनियोजित शहरीकरण और पर्यटन दबाव:** तीर्थस्थलों (केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी) में बड़े पैमाने पर होटल, सड़क और पार्किंग का निर्माण।
 - उदाहरण: जोशीमठ भूस्खलन 2023, जलविद्युत सुरंग निर्माण + अति-निर्माण से जुड़ा हुआ।
- **बुनियादी ढांचे का विस्तार:** चारधाम राजमार्ग और कई जल विद्युत बांध जैसी परियोजनाएँ नाजुक ढलानों को खंडित करती हैं।
- **वनों की कटाई और उत्खनन:** पहाड़ी कटाई, पत्थर खनन और वन विनाश प्राकृतिक ढलान स्थिरता को कम करते हैं।

- **प्रदूषण और एरोसोल:** सिंधु-गंगा के मैदान से काला कार्बन बर्फ पर जम जाता है, जिससे बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है → एरोसोल पश्चिमी विक्षोभ बादल निर्माण को बदल देते हैं, जिससे अनियमित वर्षा बढ़ जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन (मानव-चालित):** बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण हिमालय का तापमान बढ़ रहा है, जिसे "तीसरा ध्रुव संकट" कहा जाता है।

इन परिवर्तनों के प्रभाव -

- **मानव जीवन और संपत्ति की हानि:** जम्मू 2025 बाढ़ (40+ मौतें), हिमाचल 2023 बाढ़ (400 मौतें, ₹10,000 करोड़ की हानि)।
- **कृषि संबंधी नुकसान:** खेतों का बह जाना, फसल उत्पादकता में कमी, कीटों का प्रकोप।
- **पर्यटन एवं तीर्थयात्रा पर प्रभाव:** चार धाम, वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा मार्गों पर भारी व्यवधान।
- **बुनियादी ढांचे को नुकसान:** एनटीपीसी की तपोवन परियोजना (चमोली 2021) नष्ट हो गई, जिससे बांध क्लस्टरिंग के जोखिम पर प्रकाश डाला गया।
- **जल सुरक्षा जोखिम:** अनियमित नदी प्रवाह, बढ़ती हिमनद झील विस्फोट से बाढ़।
- **पारिस्थितिकी तंत्र तनाव:** जैव विविधता, वनों और पारंपरिक पर्वतीय आजीविका का नुकसान।
- **विस्थापन:** जोशीमठ जैसे पर्वतीय गांव असुरक्षित घोषित; जलवायु शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम:** लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेना के शिविरों और सीमा चौकियों को भी भूस्खलन और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (EWS) क्यों विफल हो रही हैं?

- **निम्न-रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमान:** आईएमडी की भविष्यवाणियां अक्सर जिलों को कवर करती हैं, घाटियों/ढलानों को नहीं, जिससे सूक्ष्म-स्तर की वर्षा में भिन्नताएं छूट जाती हैं।
- **अपर्याप्त निगरानी केंद्र:** सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में मौसम रडार, वर्षामापी और सेंसरों का विरल नेटवर्क।
- **कम समयावधि:** बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं कुछ ही घंटों में हो जाती हैं, जो वर्तमान ईडब्ल्यूएस क्षमता से परे होती हैं।
- **डेटा एकीकरण अंतराल:** जीएसआई भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र राज्य आपदा योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं।
- **संचार संबंधी बाधाएं:** चेतावनियां प्रायः संवेदनशील ग्रामीणों, पर्यटकों या तीर्थयात्रियों तक वास्तविक समय में नहीं पहुंच पाती हैं।

भविष्यवाणी में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?

- **सघन निगरानी नेटवर्क:** संवेदनशील घाटियों में अधिक AWS (स्वचालित मौसम स्टेशन), डॉपलर रडार और IoT सेंसर।
- **स्थानीयकृत हाइड्रोमेट मॉडल:** घाटी-विशिष्ट वर्षा-अपवाह मॉडल विकसित करना।
- **खतरा मानचित्रों का एकीकरण:** जिला आपदा योजनाओं में जीएसआई भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण और हिमनद झील निगरानी का उपयोग करना।
- **बहु-एजेंसी समन्वय:** विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन को समन्वित करने के लिए हिमालयी राज्यों की एक परिषद।
- **समुदाय-आधारित चेतावनियाँ:** तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों के लिए स्थानीय भाषाओं में एसएमएस/ऐप-आधारित चेतावनियाँ।

भविष्यवाणी में प्रौद्योगिकी और एआई की भूमिका -

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग:** एआई वास्तविक समय जोखिम पूर्वानुमान के लिए बड़े पैमाने पर डेटासेट (उपग्रह चित्र, वर्षा, मिट्टी की नमी, ग्लेशियर पिघलना) का विश्लेषण कर सकता है।
 - उदाहरण: मशीन लर्निंग आधारित "नाउकास्टिंग" मॉडल कुछ घंटों के भीतर बादल फटने की भविष्यवाणी करते हैं।
- **रिमोट सेंसिंग और ड्रोन:** ढलान निगरानी, हिमनद झील मानचित्रण और भूस्खलन का पता लगाने के लिए यूएवी।
- **IoT एवं सेंसर नेटवर्क:** प्रारंभिक चेतावनी के लिए संवेदनशील ढलानों और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में इंटरनेट से जुड़े सेंसर।
- **क्लाउडसोर्स डेटा प्लेटफॉर्म:** नागरिकों के लिए भूस्खलन या असामान्य जल स्तर की रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल ऐप, जो एआई मॉडल में फीडिंग करते हैं।
- **हिमालय के डिजिटल ट्विन:** वर्षा की सीमा, ढलान की स्थिरता और बुनियादी ढांचे की लचीलापन का परीक्षण करने के लिए घाटियों के वर्चुअल सिमुलेशन का निर्माण।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** खतरे के मानचित्रण के लिए जापान की एआई-आधारित भूस्खलन प्रणालियों और यूरोप के कोपरनिकस कार्यक्रम से सीखें।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#), [द हिंदू](#)



भारत की उर्वरक निर्भरता

संदर्भ

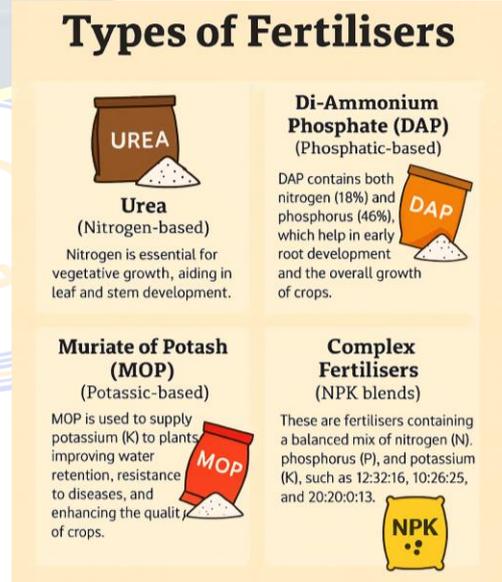
दुनिया में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद, भारत प्रमुख कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। यह निर्भरता एक आर्थिक कमजोरी और पर्यावरणीय चिंता दोनों है।

डेटा -

- वित्त वर्ष 2025 में, आयात से डीएपी की 47.5%, एमओपी की 124%, जटिल उर्वरकों की 15.2% और यूरिया की 14.6% माँग पूरी हुई।
- कुल उर्वरक आयात में 9.7% की गिरावट आई (वित्त वर्ष 2025 बनाम वित्त वर्ष 2024), लेकिन खपत रिकॉर्ड 655.94 लीटर तक पहुँच गई, जो बढ़ती माँग को दर्शाता है।
- भारत अपनी लगभग 20% यूरिया, 50-60% डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और 100% म्यूरिएट ऑफ पोटेश (एमओपी) के लिए आयात पर निर्भर है।
- **प्रमुख आयात साझेदार:** चीन, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान और मिस्र।

भारत उर्वरक आयात पर अत्यधिक निर्भर क्यों है?

- **भूवैज्ञानिक बाधाएँ:** भारत में फॉस्फेट रॉक और पोटेश के महत्वपूर्ण भंडार का अभाव है।
 - उदाहरण: म्यूरिएट ऑफ पोटेश (एमओपी) की सम्पूर्ण माँग और 80% फॉस्फेटिक कच्चे माल का आयात किया जाता है।
- **यूरिया के लिए ऊर्जा निर्भरता:** यूरिया उत्पादन फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है।
 - उदाहरण: भारत यूरिया उत्पादन के लिए अपनी गैस आवश्यकता का 77% आयात करता है (2012-13 में 24% की तुलना में)।
- **बढ़ती घरेलू माँग:** 2012-13 से उर्वरक की खपत दोगुनी से अधिक हो गई है।
 - उदाहरण: वित्त वर्ष 2025-कुल बिक्री रिकॉर्ड 655.94 लाख टन (एलटी) तक पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 600.79 एलटी थी (+9.2%)।
- **अपर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता:** एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, भारत की क्षमता माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- **सब्सिडी-संचालित माँग:** भारी सब्सिडी, विशेष रूप से यूरिया पर, अति प्रयोग और अकुशलता को बढ़ावा देती है, जिससे आयात की जरूरत बढ़ जाती है।



उर्वरक उत्पादन और आत्मनिर्भरता में चुनौतियाँ -

संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **कच्चे माल की कमी:** पोटेश और फॉस्फेट भंडार की कमी।
- **आयात-लिंकड यूरिया:** अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमतों पर निर्भर।

- **पोषक तत्वों का अनुचित उपयोग:** भारत में किसान बहुत ज्यादा यूरिया (नाइट्रोजन) और बहुत कम फॉस्फोरस (P) और पोटैशियम (K) का इस्तेमाल करते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का अस्वास्थ्यकर संतुलन बनता है (वर्तमान अनुपात 7:2.7:1 है, जबकि आदर्श अनुपात 4:2:1 है)।

आर्थिक चुनौतियाँ

- **बढ़ती सब्सिडी का बोझ:** उर्वरक सब्सिडी 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई, जिससे राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ गया।
 - बढ़ती उर्वरक सब्सिडी सरकार की राजकोषीय क्षमता को कम करती है, घरेलू उत्पादन को विकृत करती है, आयात पर निर्भरता बढ़ाती है और संरचनात्मक सुधारों में देरी करती है
- **मूल्य अस्थिरता:** भू-राजनीतिक तनाव (रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया) आपूर्ति को बाधित करते हैं और लागत बढ़ाते हैं।

शासन संबंधी चुनौतियाँ

- **खंडित प्रशासन:** उर्वरक एक अलग मंत्रालय के अधीन; कृषि एक अन्य मंत्रालय के अधीन → अकुशलता।
- **वितरण संबंधी मुद्दे:** राशनिंग, किसानों की कतारें, तथा गैर-कृषि उपयोग के लिए उपयोग।

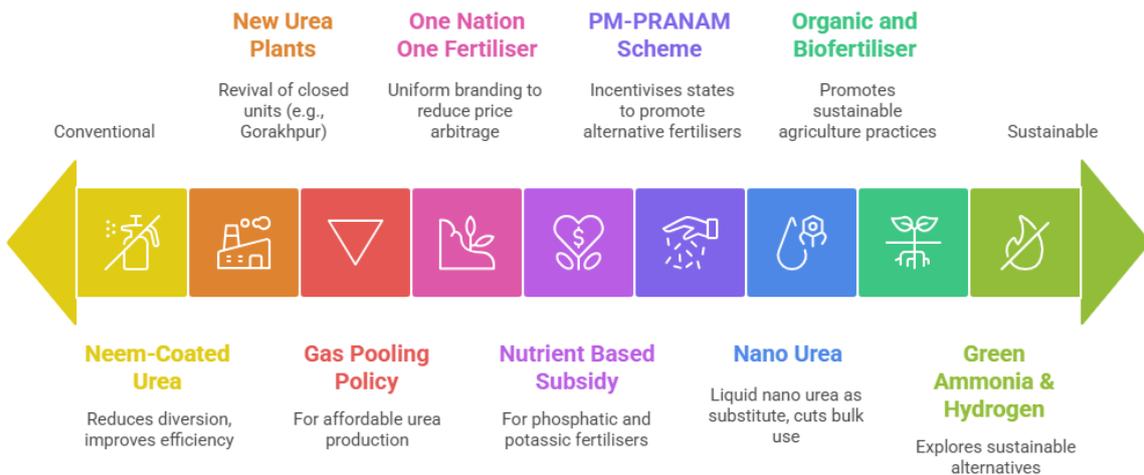
तकनीकी चुनौतियाँ

- **संयंत्रों की कम उत्पादकता:** कई संयंत्र पुराने, ऊर्जा-गहन और वैश्विक उत्पादकों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हैं।
- **विकल्पों को अपनाने में धीमी गति:** नैनो यूरिया में संभावनाएं हैं (1 बोतल = 1 बैग यूरिया), लेकिन इसे अपनाने का स्तर बढ़ाना और किसानों की स्वीकृति सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं।

विकल्प और छूटे हुए अवसर

- जैविक खाद, जैव-उर्वरक और हरित अमोनिया, रासायनिक उर्वरक के उपयोग का 30% तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नीतिगत प्रोत्साहन का अभाव है।
- सब्सिडी अभी भी रासायनिक उर्वरकों की ओर झुकी हुई है; जैविक विकल्प बौए गए क्षेत्र के <8% को कवर करते हैं।
- भारत हरित अमोनिया का उत्पादन करता है, लेकिन इसका निर्यात करता है, क्योंकि इसे अभी तक कृषि उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

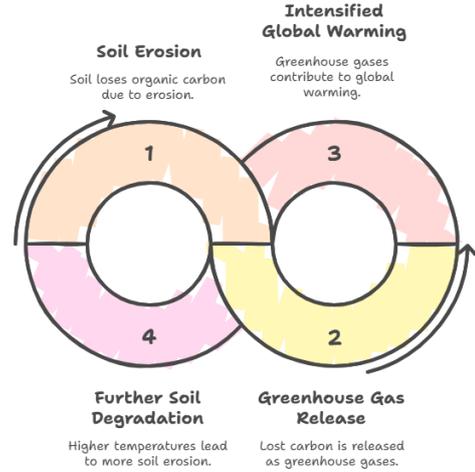
Government Initiatives



बढ़ता मृदा संकट -

- **उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग:** हरित क्रांति के बाद से, किसान उपज बढ़ाने के लिए यूरिया और डीएपी की भारी मात्रा पर निर्भर रहे हैं।
 - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है।
- **पोषक तत्व असंतुलन:** अत्यधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्व (जस्ता, सल्फर, बोरोन) कम हो गए हैं।
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के आंकड़ों से पता चलता है कि 40% भारतीय मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की कमी है।
- **घटती पैदावार:** अधिक उर्वरक उपयोग के बावजूद, उर्वरकों की सीमांत उत्पादकता गिर रही है (घटते प्रतिफल का नियम)।
- **मृदा अम्लीकरण एवं जल प्रदूषण:** यूरिया/डीएपी का लगातार उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है, सूक्ष्मजीवीय गतिविधि को कम करता है, तथा नाइट्रेट्स के साथ भूजल को प्रदूषित करता है।
- **दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा जोखिम:** यदि अत्यधिक उपयोग जारी रहा, तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इतनी खराब हो जाएगी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी, जिससे भविष्य की उत्पादकता को खतरा हो सकता है।

Soil Degradation and Climate Change Cycle



आगे की राह -

- **स्रोतों में विविधता लाना और आयात को सुरक्षित करना:** कई देशों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध (उदाहरण के लिए, फॉस्फेट के लिए जॉर्डन, मोरक्को; पोटैश के लिए कनाडा, रूस)।
- **घरेलू विकल्पों को बढ़ावा देना:** नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैव उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना।
 - घरेलू कृषि उपयोग के लिए हरित अमोनिया को मंजूरी दी जाए।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना:** रासायनिक और जैविक उर्वरकों के बीच सब्सिडी को संतुलित करना।
 - उत्पादकों के बजाय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
- **पोषक तत्वों के असंतुलन को ठीक करना:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अनुकूलित उर्वरक मिश्रण को बढ़ावा देना।
- **संस्थागत सुधार:** उत्पादन, नीति और उपयोग को संरेखित करने के लिए उर्वरक मंत्रालय को कृषि के साथ विलय करना।
- **निजी क्षेत्र और नवाचार को प्रोत्साहित करना:** मूल्य निर्धारण को उदार बनाएं और निजी खिलाड़ियों को जैविक, जैव उर्वरकों और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की अनुमति देना।

स्रोत: [हिंदू बिजनेस लाइन](#)

भारत में बुजुर्ग महिलाओं का स्वास्थ्य - एक मौन संकट

संदर्भ

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 (IIPS और UNFPA) के अनुसार, 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 20% से अधिक होगी। महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में 2.7 वर्ष अधिक जीवित रहती हैं, फिर भी, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उपेक्षित, कम अध्ययन किए गए और कम देखभाल वाले बने हुए हैं।

बुजुर्ग महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ -

सामाजिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ

- **पितृसत्तात्मक व्यवस्था** के कारण महिलाएं अपने स्वास्थ्य की अपेक्षा पारिवारिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी निर्णय अक्सर पति-पत्नी या वयस्क बच्चों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे महिलाओं की स्वायत्तता कम हो जाती है।
- **वित्तीय निर्भरता:** लगभग 60% वृद्ध महिलाओं के पास व्यक्तिगत आय का अभाव है; <20% चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में सक्षम हैं (बनाम 44% पुरुष)।
- **डिजिटल विभाजन:** बहुत कम बुजुर्ग महिलाएं डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती हैं, जिससे टेली-स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

स्वास्थ्य सेवा में पहुंच का अंतर

- **महिला डॉक्टरों और लैंगिक रूप से-संवेदनशील सुविधाओं** की सीमित उपलब्धता।
- जटिल अस्पताल प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहायता का अभाव।
- ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं को अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

रोग का बोझ और उपेक्षा

- उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर-संचारी रोग (एनसीडी) हार्मोनल बदलावों के कारण रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में अधिक गंभीर परिणाम देते हैं।
- **हड्डियों का स्वास्थ्य:** महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया से असमान रूप से प्रभावित होती हैं; फ्रैक्चर का उच्च जोखिम गतिशीलता और मानसिक स्वास्थ्य को कम करता है।
- **कैंसर:** गर्भाशय-ग्रीवा और डिम्बग्रंथि के कैंसर का अक्सर उन्नत चरणों तक निदान नहीं हो पाता।
- **न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग:** अल्जाइमर और मनोभ्रंश महिलाओं में अधिक प्रचलित हैं (लंबी उम्र और एस्ट्रोजन में गिरावट के कारण), लेकिन इनका निदान कम किया जाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** अवसाद से ग्रस्त 10 में से केवल 1 बुजुर्ग महिला ही मदद मांगती है (हेल्पएज इंडिया) क्योंकि इसके पीछे कलंक और परामर्श तक पहुंच की कमी है।

नीतिगत अंतराल -

- वर्तमान नीतियां मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जोर देती हैं, लेकिन प्रजननोत्तर स्वास्थ्य आवश्यकताओं की अनदेखी करती हैं।
- **खंडित शासन:** महिलाओं की वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों में व्यवस्थित रूप से एकीकृत नहीं किया गया है।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील वृद्धावस्था देखभाल का अभाव:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का अभाव।

आगे की राह -

- **समावेशी स्वास्थ्य नीतियां:** बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और वृद्धावस्था देखभाल योजनाओं में एकीकृत करना।

- **वित्तीय सुरक्षा:** पेंशन, बीमा कवरेज (आयुष्मान भारत) का विस्तार करें, तथा बुजुर्ग महिलाओं के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करना।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल:** महिला डॉक्टरों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण में वृद्धि।
- **निवारक देखभाल और जांच:** नियमित एनसीडी जांच, ऑस्टियोपोरोसिस जांच और जागरूकता अभियान।
 - पैप स्मीयर, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाना।
- **डिजिटल एवं सामुदायिक हस्तक्षेप:** साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल लैंगिक अंतर को पाटना।
 - आउटरीच के लिए स्वयं सहायता समूहों और आशा कार्यकर्ताओं का उपयोग करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** समुदाय आधारित परामर्श, सामाजिक सहभागिता केंद्रों का विस्तार करना, तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को कलंकमुक्त करना।

भारत की वृद्ध महिलाओं को तीन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है: लंबी उम्र, बुढ़ापे में खराब स्वास्थ्य और व्यवस्थागत उपेक्षा। स्वस्थ और सम्मानजनक वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए, भारत को लैंगिक रूप से संवेदनशील, समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियाँ बनानी होंगी, वित्तीय और डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करनी होगी और निवारक देखभाल को बढ़ावा देना होगा।

स्रोत: [द हिंदू](#)

